● वर्ष-3
● अंक-107
रायपुर, बुधवार
13 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-4›› जम्मू-कश्मीर में अब विकास....

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ महतारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

नयी सुबह
नयी सोच

अब होगा विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण

सेवा
सुशासन
सुरक्षा
विकास

सबका साथ - सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क

संवाद- 39075/119

बच्चों की हथेली जलाने के मामला में जस्टिस भादुड़ी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

कोंडागांव। माकड़ी ब्लॉक केकेरावाही मिडिल स्कूल के 25 मासूम बच्चों की हथेली पर शिक्षक द्वारा उबलते तेल की बूंदे डालने की बर्बर घटना पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में पीड़ितों को विधिक सहायता पहुंचाई जा रही है तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने कहा गया है। साथ ही प्रदेश के सभी विद्यालयों और छात्रावास में अभियान चलाकर कानून की जानकारी दी जाएगी।

जस्टिस भादुड़ी ने सालसा के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद सालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष को जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों से संपर्क किया। उनको उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई तथा विधिक सहायता, सलाह उपलब्ध कराने कहा है। छात्रों को शासन की योजना के अनुरूप आर्थिक सहायता हेतु समुचित क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाएगी तथा साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार उचित अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से स्कूलों, छात्रावासों में बच्चों, छात्रों के बीच कानून का प्रचार-प्रसार किया जाए। इस काम में न्यायाधीश, पैरालीगल वॉलिंटियर्स, एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने प्रदेश भर के बाल गृह, दत्तक गृह इत्यादि में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को प्रत्येक माह भ्रमण करने एवं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के संबंध में निर्देश दिया है।

उल्लेखनिय है कि कोंडागांव जिले के माकड़ी के समीप केरावाही के मिडिल स्कूल में बीते 9 दिसंबर को लेडीज वाशरूम में किसी ने शौच किया लेकिन पानी नहीं डाला। शिक्षिकाओं ने छात्राओं को बुलाकर पूछा कि किसने गंदगी छोड़ी है। डरी-सहमी छात्राओं में से किसी ने भी गलती नहीं मानी। तब सच उगलवाने के नाम पर स्कूल के रसोईघर में 25 छात्राओं की हथेलियों पर उबलता हुआ तेल डाल दिया। जिससे उनके हाथों में फफोले पड़ गए। घटना के पीछे प्रधान अध्यापिका जौहरी मरकाम, शिक्षिका पूनम ठाकुर, मिताली वर्मा और स्वीपर डमरू राम यादव का हाथ बताया गया है। पालकों में इस घटना से रोष है। अब शिक्षिकाएं अपने बचाव में बच्चों से कहलवा रही है कि उन्होंने खुद ही अपने हाथों पर तेल डाला था। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी का कहना है कि प्रधान अध्यापिका, दोनों शिक्षिकाओं और स्वीपर को निलंबित करने की अनुशंसा संयुक्त संचालक से की गई है।

कॉपी-किताब की जगह छात्रों के हाथ में थमाया गया झाड़ू-पोछा

बिलासपुर। आत्मानंद स्कूल में बच्चों से झाड़ू-पोछा लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में स्कूली बच्चे पढ़ाई-लिखाई की बजाय साफ सफाई करते दिख रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को गलत बताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। यह मामला सरकंडा मुक्तिधाम के सामने स्थित पंडित राम दुलारे दुबे स्वामी आत्मानंद स्कूल का है। जिले समेत शहर के कई स्कूलों का रंगरोगन कर डिजिटल क्लॉस रूम बनाकर बच्चों को बेहतर बुनियादी शिक्षा देने आत्मानंद स्कूल का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी-किताब देने के बजाए उनके हाथों में झाड़ू और पोंछा धमाकर उनसे कक्षा और स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है। शहर के सरकंडा मुक्तिधाम स्थित पंडित रामदूलारे आत्मानंद स्कूल में बच्चे सुबह पढ़ाई के बजाए स्कूल में झाड़ू-पोछा और साफ-सफाई का काम करते नजर आए। बच्चों ने बताया कि वो प्रतिदिन इसी तरह सफाई करते हैं। सुबह स्कूल की कक्षा भी नहीं लगी थी। बच्चे पहले टेबल कुर्सी को कमरे से बाहर निकालकर कक्षा में झाड़ू लगाने के बाद पोंछा भी लगाते रहे।

सुकमा में आईईडी विस्फोट डीआरजी जवान घायल

सुकमा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात जारी है। मंगलवार सुबह नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में विस्फोट होने से जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट किस्टाराम पुलिस थाना क्षेत्र के सालेतोंग गांव के पास हुआ है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, नक्सलगढ़ सालेटोंग में सीआरपीएफ का नया कैंप स्थापित किया गया है। जवान इस इलाके में डिमाइनिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी दौरान आज नक्सलियों के लगाए आईईडी में विस्फोट से यह हादसा हुआ है। जिसकी चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान का नाम जोगा है। वह डीआरजी में आरक्षक पद पर पदस्थ है।जवान के पैर में चोटें आई है। घायल जवान का उपचार नजदीकी पुलिस कैम्प में किया जा रहा है। घायल जवान की स्थित खतरे से बाहर है।

इससे पहले सोमवार 11 दिसंबर को भी आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुए थे। सोमवार को सड़क सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट किये गए प्रेशर आईईडी बम पर जवानों का पैर पड़ने से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 4 जवान घायल हुए। इनमें 2 जवानों को गंभीर चोटें आई। घायल जवानों को उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ में नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चुनावी साल में नक्सली लगातार जवानों को आईईडी ब्लास्ट में निशाना बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले और वोटिंग के दिन भी नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाया। चुनाव होने के बाद नई सरकार के गठन से पहले भी नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। सुकमा में लगातार दूसरे दिन आईईटी ब्लास्ट में जवान घायल हुए हैं। नक्सली बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सुरक्षाबल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा से ही आईडी बम का इस्तेमाल करते आए हैं। जवानों को आईईडी ब्लास्ट से काफी नुकसान भी हुआ है। आईईडी की चपेट में न सिर्फ जवान बल्कि बस्तर के ग्रामीण और मवेशी भी आ चुके हैं।

कांग्रेस समर्थित नगर पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी डगमगाई

नवागढ़ और थान खम्हरिया में विपक्ष ने लाया अविश्वास प्रस्ताव

बेमेतरा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही नगर पालिका एवं नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्षों की कुर्सी डगमगाने लगी है। कवर्धा और पंडरिया के बाद अब बेमेतरा जिला के थानखम्हरिया और नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने आवाज बुलंद कर दी है। बेमेतरा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर पीएस एल्मा को पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन सौंपा है।

थानखम्हरिया नगर पंचायत में अभी पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के करीबी माने जाने वाले तितली गौरव बिंदल अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है। उनके खिलाफ पार्षदों द्वारा यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले सत्ता पक्ष में माहौल होने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। लेकिन अब सत्ता भाजपा की है और पार्षदों ने एक बार फिर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला पार्षद अंजना ठाकुर और विजय शर्मा समेत 5 पार्षदों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है।

नवागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष तिलक घोष के खिलाफ भी पार्षदों ने बगावती तेवर दिखाए हैं। तिलक पूर्व विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के करीबी माने जाते हैं। पार्षदों ने बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा को अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन दिया है। नवागढ़ नगर पंचायत में कुल 15 पार्षद हैं, जिसमें अध्यक्ष को हटाने 10 और अध्यक्ष को बचाने 6 पार्षदों की जरूरत होती है।

कलेक्टर, बेमेतरा ने कहा दो नगरीय निकाय थान खम्हरिया एवं नवागढ़ के पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास हेतु आवेदन किया है। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों नगरीय निकाय से पांच-पांच पार्षदों ने उपस्थित होकर अध्यक्ष के खिलाफ आवेदन किया है।

गौरलतब है कि 15 सदस्य वाली थानखम्हरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष को हटाने 10 पार्षद का विरोध जरूरी है। वहीं अध्यक्ष को बचाने के लिए 6 पार्षदों की जरूरत होगी। नवागढ़ की बात करें तो यहां भी कुल 15 पार्षद हैं। जिसमें अध्यक्ष को हटाने के लिए 10 और अध्यक्ष को बचाने के लिए 6 पार्षदों की जरूरत होगी।

केशकाल में चलती बस में आग लगने से हड़कंप

■ यात्रियों ने खिड़की से कूद कर बचाई जान

कोंडागांव। केशकाल में मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे चलती बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में करीब 60 यात्री सवार थे। आग लगने के बाद यात्रियों ने दरवाजे और खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल में भर्ती कराया है। केशकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बस चालक की पतासाजी में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक, जगदलपुर से रायपुर के लिए निकली महेंद्रा की यात्री बस जब केशकाल के रावण भाटा मैदान के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक बस में आग लग गई। आग लगते ही बस चालक और परिचालक यात्रियों को बाहर निकालना छोड़ मौके से फरार हो गए। वहीं आग लगते ही बस सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री किसी तरह दरवाजे तोड़कर बाहर निकले, कुछ यात्री खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल में करवाया जा रहा है।

बस सवार यात्रियों का कहना है कि शार्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी है। यात्रियों के अनुसार, केशकाल घाटी में चढ़ते वक्त बस के सामने के हिस्से में धुआं उठता दिखा। इस बारे में बस चालक को बताया गया था, लेकिन बस चालक ने लापरवाही बरती। बस जब रावणभाठा मैदान पहुंची तो आग की लपटें उठने लगीं। यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्होंने जिस बस की टिकट बुकिंग करवाई थी, वह बस नहीं आई। इसलिए मजबूरन उन्हें दूसरी बस में सफर करना पड़ा। लापरवाही के चलते ही बस में लगी।

बस में आग लगने की वजह से यात्रियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे में यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन उनके बैग और अन्य सामान बस में ही छूट गये। जिसमें उनके कीमती गहने और जरूरी दस्तावेज थे। आग लगने से बस के अंदर मौजूद सभी समान जल गए। अब यात्रियों का कहना है कि उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए।

घटना की सूचना मिलते ही केशकाल एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और कोंडागांव से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। लगभग डेढ़ घंटे कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को बुझाया। हालांकि तब तक बस के अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि लापरवाही बरतने वाले बस मालिक और बस चालक पर किस तरह की कार्रवाई होती है।

राइस मिलरों ने समय अवधि में जमा नहीं किए 9500 मैट्रिक टन चावल

महासमुंद। जिले में राइस मिलरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां वर्ष 22-23 के कस्टम मिलिंग का 9500 मैट्रिक टन चावल जिले के 32 राइस मिलरों ने समय अवधि में जमा नहीं किए। इससे शासन को करोड़ों रुयपों की क्षति हुई। विपणन विभाग मात्र नोटिस पर नोटिस जारी कर शासन के आदेश का इंतजार कर रहा है।

महासमुंद जिले में वर्ष 22-23 में कस्टम मिलिंग के लिए 177 राइस मिलरों का पंजीयन किया गया था, जिन्हें 7 लाख 94 हजार मैट्रिक टन धान दिया गया था। राइस मिलरों को इसके एवज में 1 क्विंटल अरवा धान के बदले 67 किलो चावल व 01 क्विंटल उसना धान के बदले 68 किलो चावल जमा करना था, पर 32 राइस मिलरों ने समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त होने के बावजूद आज तक 9500 मैट्रिक टन चावल जमा नहीं किया। नियमानुसार तय समय सीमा के अंदर राइस मिलरों को चावल जमा करना अनिवार्य होता है। चावल जमा नहीं करने पर प्रशासन उन पर उचित कार्यवाही करने के साथ उनका पंजीयन नए सत्र के कस्टम मिलिंग के लिए नहीं करता है पर समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विपणन विभाग के आला अधिकारी अभी तक मात्र नोटिस ही जारी करने की बात कह रहे हैं। यही कारण है कि वर्ष 23-24 के कस्टम मिलिंग मे प्रशासन को दिक्कत आ रही है और धान समितियों मे डंप पड़ा है और समितियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले मे वर्ष 23-24 के लिए 01 नवंबर से अभी तक 252784 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और 116000 मैट्रिक टन धान का कस्टम मिलिंग हो पाई है। शेष 136784 मैट्रिक टन धान अभी भी धान उपार्जन केन्द्रों में खुले आसमान में पड़ा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

खड़गवां वनपरिक्षेत्र के फुनगा गांव में हाथियों का आतंक

कोरिया। खड़गवां वनपरिक्षेत्र में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है।हाथी ग्रामीणों की फसल बर्बाद कर रहे हैं।जिसके बाद ग्रामीण और गोंड समाज के लोग अपनी फरियाद लेकर वनमंडल अधिकारी के पास पहुंचे।जहां वन मंडल अधिकारी ने ग्रामीणों की बात सुनी। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से वन परिक्षेत्र खड़गवां के फुनगा गांव में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है।कुछ दिनों तक हाथी का एक दल ग्रामीणों की फसल को नुकसान पहुंचा रहा था।वहीं अब दूसरे हाथी भी फुनगा गांव के पास आ गए हैं।जिसके बाद अब ग्रामीणों को लगने लगा है कि उनकी जान और फसल दोनों ही खतरे में है।इसलिए सभी ग्रामीण मदद के लिए वनमंडल अधिकारी के पास पहुंचे थे। परेशान ग्रामीण लगातार खड़गवां वनपरिक्षेत्र के अफसरों से इसकी शिकायत कर रहे थे।लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद परेशान ग्रामीण मंगलवार को पूरे समाज के साथ बैकुंठपुर वन मंडल अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने हाथियों को गांव की सीमा से बाहर करने की मांग की है।

नगरनार में एनएमडीसी प्लांट से निकल रहा जहरीला पानी

जगदलपुर। सालों से जिस समस्या को कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं उठाया, उन समस्याओं को कांग्रेस से स्थानीय नेताओं ने उठाना शुरु कर दिया है। ताजा मामला एनएमडीसी स्टील प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि सालों से नगरनार में प्लांट से गंदा और जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। जहरीले पानी से खेत जहां बंजर हो रहे हैं वहीं जलस्तर भी जहरीला होता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक कभी भी पीड़ित किसानों के बीच सुध लेने नहीं गए। कांग्रेस का आरोप है कि करीब 200 एकड़ की जमीन किसानों की बंजर होने के कगार पर है। कांग्रेस नेता सुशील मौर्य का आरोप है कि प्लांट के पास जो तीन तालाब हैं उसका पानी भी जहरीला हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर समय रहते किसानों की सुध नहीं ली जाती है तो वो आंदोलन करके के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग उठाई है।

नक्सलियों ने 23वीं वर्षगांठ मनाने का वीडियो किया जारी

बीजापुर। नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया था, इसी समारोह का एक वीडियो नक्सलियों ने जारी किया है, वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबन्द नक्सलियों के साथ ग्रामीण और संगठन में नई भर्ती हुए आदिवासी युवा भी पीएलजीए वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान नक्सलियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, अमेरिका और इजरायल के प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया है। जारी वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों के साथ ग्रामीण नजर आ रहे हैं तो दूसरे वीडियो में नक्सली नेता मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजापुर और सुकमा के सीमा इलाके में मनाया गया यह समारोह किस गांव में मनाया गया यह स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों द्वारा बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में मनाये गये आयोजन का विडियो जारी किया है। इन विडियो/तस्वीरों में बड़ी संख्या में हथियारबन्द नक्सली ग्रामीणों के साथ समारोह पूर्वक वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं।

नक्सलियों ने 22 दिसम्बर को भारत बंद किया एलान

जगदलपुर। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल के प्रवक्ता समता ने प्रेस वक्तव्य जारी कर बिहार-झारखण्ड क्रांतिकारी आंदोलन पर पिछले 22 महीनों से सिल-सिलेवार ढंग से हो रहे दमन के विरोध में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने 16 से 22 दिसम्बर तक दमन विरोधी प्रतिरोध सप्ताह और 22 दिसम्बर को भारत बंद का एलान किया है। नक्सली प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि भाजपा सरकार खुलेआम संविधान को उल्लंघन कर रहे है, इसलिए इसको उखाड़ फेंककर मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गों की गठबंधन सरकार बनाना चाहिए। इस गठबंधन सरकार क्रांतिकारी सशस्त्र आंदोलन से ही बनेगी। प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि झारखण्ड ऐसे राज्य है कि देश का 40 प्रतिशत खनिज संपत्ति इसी राज्य में है। टाटा, जिंदल, मित्तल, अम्बानी, अदानी, बिरला, एर्टेल, वेदंता जैसे कॉरपोरेट कम्पनियों द्वारा लूटा जा रहा है। पिछले 20 महीनों से बिहार-झारखण्ड का आदिवासी गांवों पर हो रहे 81 एमएम आर्टीलरी बम से जनता भयभीत हो रहे हैं।

साइबर अटैक, व्हाट्सएप हैक कर लाखों रुपये की ठगी

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के बेरला थाना में व्हाट्सएप एप को हैककर 1.43 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में बेरला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420, 66 (घ) के तहत मामला दर्ज किया है। थाना से मिली जानकारी अनुसार इस मामले में प्रार्थी अभिषेक जैन पिता विजय जैन उम्र 28 निवासी वार्ड क्रमांक 3 ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपने आवेदन में बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके व्हाट्सएप एप को हैक कर उनके परिचित के तीन व्यापारियों से एक लाख 43 हजार 800 रुपए ट्रांसफर कर लिए है। जब इस बात की जानकारी प्रार्थी अभिषेक को लगी तो थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में लगी हुई है। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले में इस तरह किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप एप को हैक कर ठगी का यह पहला मामला है।

डॉक्टर-कर्मचारी के बीच मारपीट, विरोध में उतरा स्टाफ

■ विवादों में है कोरकोमा का स्वास्थ्य केंद्र, अब होगी जांच

कोरबा। कई कारणों से विवादों में बने कोरकोमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित और एक महिला कर्मचारी ने मारपीट करने का दावा किया है। जबकि डॉक्टर इससे साफ इनकार कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मौके पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने बताया कि तथ्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

विकासखंड कोरबा के अंतर्गत कोरबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। जहां पर फार्मासिस्ट सखाराम पैकरा से टेबल हटाने की बात को लेकर डॉ. एमएल भारिया ने मारपीट की। फार्मासिस्ट सखाराम पैकरा ने बताया कि आयुष्मान विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ है। आज सुबह जब ड्यूटी पर पहुंचे और उसके बाद डॉक्टर एमएल भारिया टेबल और कुर्सी को अंदर रखने के लिए कहा कि अकेले होने के कारण वह अंदर नहीं कर पाए। जब चपरासी अंदर आया उसके बाद अंदर करने जा ही रहा था इस दौरान पीछे से आकर उसे मार दिया और वह जमीन पर गिर गया। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और इसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों को दी।

अस्पताल की एक सफाई कर्मचारी ईशा राठिया ने बताया कि टेबल हटाने की बात पर विवाद के बाद यह घटना हुई। एमएल भारिया ने मारपीट की है। डॉ भारिया ने बताया कि शनिवार को कायाकल्प योजना की बैठक के बाद एक स्थान से टेबल हटाने के लिए उन्होंने सखाराम को कहा था। पहले उसने मना किया और बाद में विवाद शुरू कर दिया। पहले उसने हाथ उठाया और मैंने बचाव किया तभी वह गिर पड़ा। मैंने उससे कोई मारपीट नहीं की है।

स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट होने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले की जांच के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक सिंह राज पहुंचे। उन्होंने बताया कि कर्मचारी और डॉक्टर से पूछताछ की गई है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि इससे पहले भी यहां पर कई तरह की शिकायत मिली थी। जिसके बाद इंक्रीमेंट रोकने की अनुशंसा की गई थी। यह बताना आवश्यक होगा कि लंबे समय से कोरकोमा का स्वास्थ्य केंद्र विवादों में बना हुआ है। देखना होगा कि यहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।

ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

■ सात सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

कबीरधाम। मंगलवार को कबीरधाम जिले में ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। दोपहर को अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौपा है। जानकारी अनुसार, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है।

संघ के नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन और आवेदन दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा केवल आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। खाली हाथ रिटायर होना मंजूर नहीं है। संघ की प्रमुख रूप से सात मांगे हैं,जिनमे आठ घंटे का काम, पेंशन, कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश को लागू करना, ग्रामीण डाक सेवक की एसडीबीएस में सेवा निर्वहन लाभ तीन फीसदी से बढ़कर दस फीसदी करने, सभी प्रकार की प्रोत्साहन योजना को समाप्त कर जैसे आइपीपीबी, आरपीएलआइ, बचत योजना, मनरेगा भुगतान को बंद कर कार्यभार की गणना की जाए।

इधर, मंगलवार से हड़ताल शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की डाकसेवा प्रभावित है। कबीरधाम जिले के करीब 100 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल में शामिल है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों में ताला लटका है। हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्ठी पत्रों का वितरण नहीं हो रहा है।

● वर्ष-3
● अंक-107
रायपुर, बुधवार
13 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-4›› जम्मू-कश्मीर में अब विकास....

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ महतारी

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

आज होगी शुरूआत

विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़

के निर्माण की

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

की गरिमामयी उपस्थिति में

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री

श्री विष्णु देव साय

एवं

मंत्रिमण्डल के सदस्यगण आज लेंगे

शपथ

सेवा की | सुशासन की | सुरक्षा की | विकास की

दिनांक- 13 दिसम्बर, 2023
स्थान- साईंस कॉलेज मैदान, रायपुर
समय- दोपहर 2.00 बजे

सबका साथ-सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

संवाद- 39068/118

गलतियों को नहीं मानना कांग्रेस की हार की वजह

सुरेश हिंदुस्तानी

चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद तस्वीर उभरी है, उससे एक बात फिर साबित हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वास्तव में जीत की गारंटी बन गए हैं। उत्तर भारत के तीन बड़े राज्यों के चुनाव प्रचार और अन्य प्रचार माध्यमों का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रादेशिक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित नहीं किया, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही भाजपा चुनावी मैदान में उतरी। आज पूरे देश में मोदी भाजपा के एक मात्र ऐसे चेहरे हैं, जिनसे मतदाताओं की सीधा जुड़ाव हो जाता है। वे अपनी सरकार के माध्यम से धरातल से जुड़ते हैं। इन चुनावों में सबसे बड़ा तथ्य यही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास प्रचार करने वाले नेताओं की बेहद कमी थी। भले ही कांग्रेस इस बात का दावा करती दिखाई दी कि वह फिर से सरकार बना रही है, लेकिन परिणामों के बाद कांग्रेस के वादे और दावों की हवा निकल गई। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से विश्वास जताया है, वह 2024 के लोकसभा चुनावों की राह को आसान करने वाला ही होगा। कांग्रेस ने इन चुनावों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक नायक की तरह फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके यह प्रयास सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके। कांग्रेस का यह प्रयास शायद इसलिए भी था, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रस्तुत करने का सपना देख रही थी। इसी के साथ विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस के नेता प्रमुख दल की हैसियत बनाना चाहती थी। चुनावों के बाद कांग्रेस की पराजय ने एक बार फिर से गठबंधन के बीच दरार पैदा होने की स्थितियां निर्मित कर दी हैं। इसके पीछे का एक मात्र कारण यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता आज भी अपनी गलतियों पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, जबकि सत्य यही है कि पिछले दस सालों में कांग्रेस ने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की विजय और कांग्रेस की पराजय के कई निहितार्थ हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस सनातन के विरोधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती दिखाई दी। वर्तमान में जब भारत में देश भाव की प्रधानता विस्तारित होती जा रही है, तब स्वाभाविक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि अब देश के विरोध को जनता किसी भी रूप में स्वीकार करने वाली नहीं है। यह सही है कि जो सनातन को मिटाने का प्रयास करेगा, वह निश्चित ही आत्मघाती कदम कहा जाएगा। यहां विचारणीय तथ्य यह भी है कि जो भारत को मजबूत बनाने की राजनीति करेगा, उसे सनातन से जुड़ना ही होगा। जो मोहब्बत की भाषा बोलकर चुनाव लड़ेगा, उसे हिंदुत्व से तालमेल रखना ही होगा। सनातन का विरोध करने वाली राजनीति के आधार पर देश भाव का प्रकटीकरण नहीं हो सकता।

जम्मू-कश्मीर में अब विकास, लोकतंत्र की स्थापना

नरेंद्र मोदी

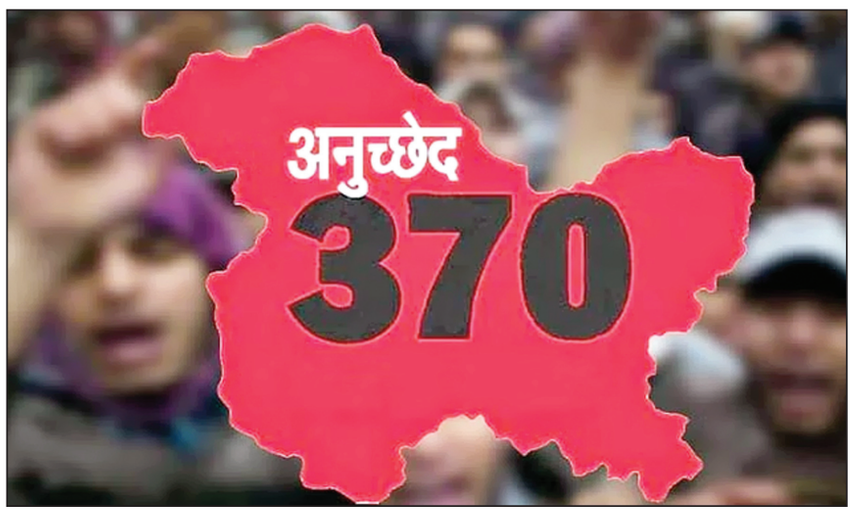

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारत की संप्रभुता और अखंडता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि पांच अगस्त, 2019 को हुआ निर्णय सांविधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य को भी भलीभांति माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था।

मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है। जम्मू-कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ था और वह काफी लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे। फिर भी, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे का कठिन रास्ता चुना, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए।

कई वर्षों बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में 'इंसानियत', 'जम्हूरियत' और 'कश्मीरियत' का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ था, वह हमारे राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे जरूर करूं।

अनुच्छेद 370 और 35 (ए) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। इनके कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को वह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया, जो उनके साथी देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेदों के कारण, एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था- जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं तथा वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो। जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय, हमने तीन बातों को प्रमुखता दी- नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी-विश्वास का निर्माण करना तथा विकास, निरंतर विकास को प्राथमिकता देना।

मुझे याद है, वर्ष 2014 में हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे कश्मीर घाटी में बहुत नुकसान हुआ था। सितंबर, 2014 में, मैं स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर गया और पुनर्वास के लिए विशेष सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा भी की। इससे लोगों में यह संदेश भी गया कि संकट के दौरान हमारी सरकार वहां के लोगों की मदद के लिए कितनी संवेदनशील है।

मुझे जम्मू-कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने का अवसर मिला है और इन संवादों में एक बात समान समान रूप से उभरती है-लोग न केवल विकास चाहते हैं, बल्कि वे दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते हैं। उस साल मैंने जम्मू-कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों की याद में दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया। मैंने दीपावली के दिन जम्मू-कश्मीर में मौजूद रहने का भी फैसला किया।

जम्मू एवं कश्मीर की विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमने यह तय किया कि हमारी सरकार के मंत्री बार-बार वहां जाएंगे और वहां के लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इन लगातार दौरों ने भी जम्मू एवं कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उद्योग को सहायता प्रदान करने से जुड़ी पहल शामिल थीं।

हमने खेल शक्ति में युवाओं के सपनों को साकार करने की क्षमता को पहचानते हुए जम्मू-कश्मीर में इसका भरपूर सदुपयोग किया। विभिन्न खेलों के माध्यम से, हमने वहां के युवाओं की आकांक्षाओं और उनके भविष्य पर खेलों से जुड़ी गतिविधियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा। स्थानीय स्तर पर फुटबॉल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना इन सबमें एक सबसे अनूठी बात रही। इसके परिणाम शानदार निकले। मुझे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी अफशां आशिक का नाम याद आ रहा है। वह दिसंबर, 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उसने फुटबॉल की ओर रुख किया, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव भी इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। पंचायत चुनावों की सफलता ने जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति को इंगित किया।

पांच अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया और तब से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी डर या पक्षपात के लागू होते हैं, प्रतिनिधित्व भी पहले से अधिक व्यापक हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है, बीडीसी चुनाव हुए हैं, और शरणार्थी समुदाय, जिन्हें लगभग भुला दिया गया था, उन्हें भी विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। आवास, नल से जल कनेक्शन और वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। सरकारी रिक्तियां, जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात का शिकार होती थीं, पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत भरी गई हैं। बुनियादी ढांचे और पर्यटन में बढ़ावा सभी देख सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में मोहभंग, निराशा और हताशा की जगह अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा ने ले ली है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग (मूल) प्रकाशमय और वाणी से परे है, इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद् है। दोनों नेत्रों के बीच जाग्रत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। स कार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वं का स्वरूप है।

ह कार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत पद के रूप में है। जो भी प्राणी स कार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से ह कार रूप हो जाता है। यही सोऽहम् और तत्त्वमसि की साधना है। [ऋषि यहाँ सोऽहम और तत् त्वम बोध वाक्यों की समानता एकरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं।

साधक जब तात्त्विक दृष्टि से स्व की ओर देखता है, तो सोऽहमस्मि का बोध करता है तथा जब बाहर की ओर उसी दृष्टि से देखता है, तो तत्त्वमसि का अनुभव करता है।] जीव को इन्द्रियाँ बन्धन में बाँधती हैं, आत्मा को इन्द्रियाँ नहीं बाँध सकती हैं। जब तक ममता होती है, वह जीव रहता है, ममता के बन्धन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है।

सूर्य, चन्द्र और अग्नि देवता एवं भूः भुवः स्वः लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं, वह परम प्रकाशरूप ओंकार है। परम प्रकाशमान ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियाँ विराजमान हैं। सदैव वाणी से उसका जप करे तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप करते हुए उसी परमप्रकाशरूप ओंकार में स्थिर हो जाए। पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप-पंक में नहीं फँसता, संसार में वह जल से अलिप्त पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है।

क्रमशः..

महाराजा छत्रसाल

इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जो धुंधले हो चुके हैं या शायद हम ही उनके विषय में पढ़ने और जानने का प्रयास नहीं करते। उन्हीं नामों में से एक है छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल बुंदेला एक भारतीय शासक और बुंदेला राजपूत कबीले के सदस्य थे। यह इतिहास का वो नाम है जिसने मुगल साम्राज्य का विरोध किया और अपने शासनकाल के अंत तक बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। आइए महाराजा छत्रसाल के बारे में महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर लेते हैं।

छत्रसाल का जन्म 1649 ईस्वी में कछार कचनाई यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम चंपत राय और उनके माता का नाम लाल कुंवर था। उनके पिता एक बुंदेला सरदार थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था जिनकी मृत्यु 1661 में हुई थी। एक युवा के रूप में, उन्हें मुगल कमांडर मिर्जा राजा जयसिंह के अधीन ले जाया गया और यहां तक कि मराठा के खिलाफ मुगल अभियानों में भी काम किया और उनकी बहादुरी से कई मनसब जीते।

अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में, प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि कैसे छत्रसाल ने मुगल शिविर को छोड़ने और मराठा राजधानी में छत्रपति शिवाजी से मिलने के लिए शिकार यात्रा के बहाने का इस्तेमाल किया। उन्होंने महान गुरिल्ला योद्धा से उन्हें नियुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें योद्धा ने सलाह दिया कि वे अपने वतन लौट जाएं और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें।

युवा छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी की सलाह मानी और बुंदेलखंड वापस लौट आए। वहां उन्होंने पन्ना के जंगलों में एक शिविर स्थापित किया और एक छोटी सेना खड़ी की जिसके साथ उन्होंने मुगल किलों पर हमला किया।

उनकी बहादुरी ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। केवल 22 साल की उम्र में, उन्होंने सिर्फ पांच घुड़सवारों और 25 पैदल सैनिकों की एक टीम के साथ मुगल सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी को हरा दिया। जल्द ही, उसका राज्य पूर्व में पन्ना और पश्चिम में ग्वालियर तक फैल गया। इसके बाद के वर्षों में, छत्रसाल ने बुंदेलखंड में मुगलों की उपस्थिति के खिलाफ लड़ना कभी नहीं छोड़ा।

अपने लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना के लिए अत्यधिक सम्मानित थे छत्रसाल। उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर संत प्राणनाथ ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, माना जाता है कि इस संत ने राजा को वरदान दिया था कि हीरे हमेशा आपके राज्य में पाए जाएं। इसी से पन्ना की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खानों की खोज हुई। 1700 में औरंगजेब ने महाराजा छत्रसाल को वश में करने के लिए कई प्रयास किए लेकिन हर बार हार गया। दरअसल, 1730 में मुगलों ने अपने प्रसिद्ध पठान योद्धा मोहम्मद खान बंगश को बुंदेलखंड भेजा था। हालांकि छत्रसाल अब वृद्ध हो चुके थे लेकिन तब भी उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम की मदद से मुगलों पर अंतिम जीत हासिल की।

विष्णुदेवः भाजपा ने देशभर के आदिवासी वर्ग को साध लिया है

ललित गर्ग

विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीवंत आदिवासी समाज को उन्नति के नये शिखर एवं राजनीति में समुचित प्रतिनिधि देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने इस समुदाय की आशाओं पर खरे उतरने की कोशिश की है। निश्चित ही विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से आदिवासी समुदाय में खुशी जगी है, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा में भी भाजपा को लाभ मिलेगा, वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के आदिवासी समुदाय के लोगों भी प्रभावित किया जा सकेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विष्णुदेव साय का निर्णय नया राजनीतिक धरातल तैयार करेगा एवं नयी राजनीतिक दिशाओं को उद्घाटित करेगा।

जमीन से जुड़े, विनम्र, ईमानदार एवं सादगीप्रिय विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की दूरगामी सोच एवं राजनीतिक परिपक्वता से जुड़ी साहसिक एवं करिश्माई राजनीति की निष्पत्ति है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विष्णुदेव साय इसलिए बड़ा नाम है, क्योंकि अब तक चार बार के सांसद, तीन बार के विधायक और छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष की कमान एवं केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 26 साल की उम्र में ही पहली बार विधायक बनने वाले विष्णुदेव के दिवंगत दादा बुधनाथ साय 1947 से 1952 तक विधायक रह चुके हैं। उनके दिवंगत ताऊ नरहरि प्रसाद साय भी दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। विष्णुदेव साय ने ताज़ा चुनाव कुनकुरी विधानसभा सीट से लड़ा था, जिसमें उन्होंने 25 हजार 541 वोटों से जीत दर्ज की। कम बोलने और बेहद विनम्र माने जाने वाले विष्णुदेव साय को, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। निश्चित ही उनकी मुख्यमंत्री की पारी ऐतिहासिक, अविस्मरणीय एवं राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण बनेगी। 21 फरवरी 1964 को एक आदिवासी परिवार में जन्में विष्णुदेव साय ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी के लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल से की है।

अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा भी था, विष्णुदेवजी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को भाजपा आपके सामने लाई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने का अपना वायदा इतना जल्दी पूरा कर दिया है। वैसे भी 32 फ़ीसद आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 17 पर भाजपा के कब्ज़े के बाद माना जा रहा था कि किसी आदिवासी विधायक को भाजपा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्षी पार्टी के नेताओं के घरों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हो रही है। झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड और 500 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है। इसलिये भाजपा ईमानदार नेताओं को आगे लाना चाहती है, विष्णुदेव साय जमीन से जुड़े हैं, आदिवासी हैं और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर हैं। ऐसे में वे भाजपा के इस कैटेगरी में एकदम फिट बैठे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी। ईमानदारी के साथ विनम्रता भी उनकी बड़ी विशेषता है। एक दिन पहले उन्होंने कहा- विनम्रता को कमज़ोरी नहीं मानना चाहिए। मैं तो इसे अपनी ताक़त मानता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि आजीवन विनम्र बना रहूं।

राजनीतिक स्वार्थ के चलते आजादी के बाद से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है जिससे उनकी जिन्दगी अभावग्रस्त ही रही है। कांग्रेस ने आदिवासी के नाम पर सत्ता तो अनेक बार हासिल की, लेकिन उनके कल्याण के लिये कोई ठोस काम नहीं किये। जबकि आदिवासी समुदाय को कांग्रेस विचारधारा का ही माना जाता रहा है, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने अपनी सूझबूझ एवं विवेक से आदिवासी लोगों का दिल जीता है। वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री रहते नरेन्द्र मोदी गुजरात के आदिवासी इलाके कवांट में जैन संत गणि राजेन्द्र विजयजी के नेतृत्व में एक समारोह में 15 हजार करोड़ की वनबंधु योजना की शुरुआत की। इन दिनों इन्हीं जैन मुनि की चर्चा चुनाव सभाओं में एवं गुजरात की एक सभा में प्रधानमंत्री ने की। उनके मन में आदिवासी कल्याण की भावना है। राजनीति जोड़तोड़ की दृष्टि से देखा जाये तो कांग्रेस जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एवं तुष्टिकरण कर रही है तो भाजपा के लिये आदिवासी समुदाय ही रौशनी बनते हुए दिख रहे हैं। निश्चित ही आगामी लोकसभा चुनाव में इन आदिवासी वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है।

जब भाजपा हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, ऐसे में आदिवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आदिवासियों में एक बड़ी समस्या धर्म परिवर्तन की है। प्रलोभनों एवं साम्प्रदायिक ताकतों के कारण कई आदिवासी अपने धर्म को बदलकर आदिवासी समाज से बाहर हो रहे हैं जिसमें ईसाई धर्म को सर्वाधिक स्वीकार गया है। ईसाई मिशनरियों ने भारत के आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र में धर्मांतरण के लिये विद्यालयों एवं छात्रावासों में सफल अभियान चलाया है। ऐसे में आदिवासी की अपनी संस्कृति एवं उनका अस्तित्व खतरा में आ गया। आदिवासी अर्थात जो प्रारंभ से वनों में रहता आया है। करीब 400 पीढ़ियों पूर्व सभी भारतीय वन में ही रहते थे और वे आदिवासी थे परंतु विकासक्रम के चलते पहले ग्राम बने फिर कस्बे और अंत में नगर, महानगर। यहीं से विभाजन होना प्रारंभ हुआ। जो वन में रह गए वे वनवासी, जो गांव में रह गए वे ग्रामवासी और जो नगर में चले गए वे नगरवासी कहलाने लगे। भारत में लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र है, इसके अधिकांश हिस्से में आदिवासी समुदाय रहता है। लगभग नब्बे प्रतिशत खनिज सम्पदा, प्रमुख औषधियां एवं मूल्यवान खाद्य पदार्थ इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में हैं। भारत में कुल आबादी का लगभग 11 प्रतिशत आदिवासी समाज है। इसी बड़ी आबादी को प्रभावित करने के लिये द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना एवं विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की परिपक्व राजनीति को दर्शाता है। विष्णुदेव साय का निर्णय राज्य में आदिवासी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए सामने आया है। इससे पहले भी आदिवासी वोटर को साधने के लिए भाजपा ने कई सकारात्मक घोषणाएं की हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा एक सोची-समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे अनेक महान् आदिवासी हुए हैं जिन्होंने भारत की मिट्टी एवं उसके स्वतंत्र अस्तित्व-आजादी के लिए अपना बलिदान एवं महान योगदान दिया। ऐसे महान वीर आदिवासियों से भारत का इतिहास समृद्ध है, जिनमें अप्पा साहब, तात्या टोपे, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुण्डा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गंडाधुरा, शहीद रानी दुर्गावती, शहीद बिरसा मुंडा, शहीद सिद्धों, कानु, शहीद तिलका मांझी, शहीद गेंद सिंह, झाड़ा सिरहा जैसे महान आदिवासियों ने अपना बलिदान देकर समाज एवं देश के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। फिर क्या कारण है कि इस जीवंत एवं मुख्य समाज को देश की मूल धारा से काटने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। आजादी के बाद बनी सभी सरकारों ने इस समाज की उपेक्षा की है। यही कारण है कि यह समाज अनेक समस्याओं से घिरा है। भाजपा आदिवासी समाज के अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाने के प्रयासों को नियंत्रित करने एवं सक्रिय होकर आदिवासी कल्याण की योजनाओं को लागू करने में जुटी है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम होगा। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में फिर आदिवासी कार्ड खेला है। विष्णुदेव साय प्रभावी आदिवासी नेता हैं और आदिवासी समुदाय में उनकी बड़ी पकड़ है। भाजपा रणनीति के तहत आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है जिसके चमत्कारी परिणाम आयेंगे।

आज का इतिहास

1774 अमेरिकी क्रांति की पहली घटना - 400 हमले एफटी विलियम और मैरी पर न्यू हैम्पशायर में हुए।
1779 एलेक्जेंडर, विकोमेट डे बेउहर्नैस ने जोसेफिन टेसर से शादी की।
1795 वोल्ड न्यूटन उल्कामी- इंग्लैंड के यॉर्कशायर में एक गांव, वोल्ड न्यूटन पर एक उल्कापात हुआ।
1843 बसुतोलांड एक ब्रिटिश संरक्षक बनाये गए।
1884 पर्सी एवरिट ने सिक्का डालकर वजन बताने वाली मशीन का पेटेंट कराया।
1916 आस्ट्रिया के टायरॉल में हिमस्खलन से 24 घंटे में 10,000 ऑस्ट्रियाई और इतालवी सैनिकों की मौत हुई।
1920 नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ।
1937 दूसरे चीन-जापानी युद्ध-जापानी सेना ने नानजिंगचाइना पर कब्जा कर लिया और फिर अगले कई स्थानों पर कई अत्याचार करने लगे।
1959 आर्क विशप वकारियोस साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए।
1960 इथियोपिया के सम्राट हैली सेलासी को देश से बाहर करने के साथ, चार षड्यंत्रकारियों ने तख्तापलट की कोशिश की और क्राउन प्रिंस असफॉ वोसन को नए सम्राट के रूप में स्थापित किया।
1967 ग्रीस के राजा कॉन्स्टेंटिने द्वितीय ने देश छोड़ दिया जब उनके तख्तापलट का प्रयास विफल हो गया।
1981 पोलिश प्रधान मंत्री वोज्शिएक जारुज़ेल्स्की ने मार्शल लॉ घोषित किया, एकजुटता को निलंबित कर दिया और कई यूनियन नेताओं को कैद कर लिया।
1989 द ट्राइबल्स-प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड के काउंटी फरमानाग में एक वाहन चेकपॉइंट कॉम्प्लेक्स में किंग्स ओन स्कॉटिश बॉर्डरर्स के साथ एक भयंकर देवदार एफआईईटी लगी।
1996 कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गये।
2002 यूरोपीय संघ का विस्तार किया गया। साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातेविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोविनिया इसमें शामिल किए गए।
2005 न्यू जर्सी में एक आवासीय इमारत के ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई और धुएं के गुबार हवा में उड़ गए।
2006 सोशल ओपिनियन सेंटर ऑफ़ उज्बेकिस्तान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 93.7% उत्तरदाताओं ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और 3.9% ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, हालांकि केवल 39.4% ने कहा कि उनके पास ऐसी स्थितियां हैं जो उनकी धार्मिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं।
2008 जम्मू-कश्मीर के पाँचवें चरण के लिए 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान हुआ।
2008 चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच एक बैठक वित्तीय संकट की वापसी के लिए क्योसो द्वीप पर हुई।

● वर्ष-3
● अंक-107
रायपुर, बुधवार
13 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-4›› जम्मू-कश्मीर में अब विकास....

आज पूरी दुनिया के सामने डीपफेक का चैलेंज

जीपीएआई समिट में बोले मोदी

विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता एआई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नयी दिल्ली में 'कृत्रिम मेधा (एआई) पर वैश्विक साझेदारी' सम्मेलन में कहा कि कृत्रिम मेधा पर हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत एआई का उपयोग करके स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने पर काम कर रहा। एआई सतत विकास में भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि डीप फेक का चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट, आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है।

मोदी ने कहा कि आज, भारत एआई और उसके उपसमुच्चय के क्षेत्र में अग्रणी है। हम एआई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में, हमने कृषि में एक एआई चेक पोर्टल लॉन्च किया है, जो किसानों को उनके आवेदन की स्थिति की जांच करने, भुगतान विवरण तक पहुंचने और सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से सूचित रहने की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत में, हम एआई नवाचार की भावना देख रहे हैं। आज भारत द्ध प्रतिभा और एआई से संबंधित नए विचारों में सबसे प्रमुख खिलाड़ी है। भारत के युवा तकनीकी विशेषज्ञ और शोधकर्ता सीमाएं तलाश रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हमारा विकास मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकारी नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सामाजिक विकास और समावेशी विकास के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना है। भारत एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज, भारत एआई और उसके उपसमुच्चय के क्षेत्र में अग्रणी है। हम एआई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में, हमने कृषि में एक एआई चेक पोर्टल लॉन्च किया है, जो किसानों को उनके आवेदन की स्थिति की जांच करने, भुगतान विवरण तक पहुंचने और सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से सूचित रहने की सुविधा प्रदान करता है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई की विकास यात्रा जितनी अधिक समावेशी होगी, समाज उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। पिछले दशकों से सीखते हुए जहां प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता थी, अब हमें समाज को इस तरह के नुकसान से बचाना चाहिए। जब लोकतांत्रिक मूल्य प्रौद्योगिकी से जुड़ते हैं, तो यह समावेशिता के लिए गुणक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि एआई के कई सकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो चिंता का विषय है। 21वीं सदी के विकास में आईए सबसे बड़ा टूल बन सकता है। लेकिन ये 21वीं सदी को तबाह करने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभा सकता है... डीपफेक पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है...एआई टूल्स का आतंकियों के हाथ में जाना भी एक बड़ा खतरा है. यदि आतंकवादी संगठनों को एआई हथियार मिलते हैं, तो इसका वैश्विक सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा... हमें योजना बनाने की जरूरत है कि इससे कैसे निपटा जाए।

नए मुख्यमंत्री आज लेंगे शपथ, मोदी होंगे शामिल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बुधवार को शपथ ग्रहण लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बुधवार सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कैबिनेट मंत्रियों को शपथ लेते देखने के लिए मौजूद रहेंगे. उस दिन बाद में, पीएम मोदी रायपुर जाएंगे जहां वह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी टीम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह शाम 4:00 बजे होगा।

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसम्बर को दोपहर दो बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि बुधवार को विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। भाजपा ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके आदिवासी नेता साय (59) को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना। नये मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और क्या राज्य में दो उप मुख्यमंत्री होंगे, इन अटकलों के बीच साव ने कहा, ''शपथ लेने वाले नेताओं की संख्या के बारे में समय आने पर जानकारी मिल जाएगी।''

मध्य प्रदेश में मोहन यादव- मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य की नई सरकार का शपथ समारोह बुधवार को होगा। यादव ने भोपाल में कहा कि शपथ समारोह परसों 13 दिसंबर को होगा। यादव के साथ-साथ मनोनीत उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। मनोनीत सीएम ने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जी रही हैं। समारोह के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता, खासकर यादव के गृहनगर उज्जैन से इकट्ठा होंगे।

चौहान का नहीं बन पाया रिकॉर्ड - कई दिनों से चल रहे अटकलों को खत्म करते हुए, भाजपा ने सोमवार को यादव को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना और पार्टी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को रिकॉर्ड पांचवीं बार सत्ता में आने से रोक दिया। चौहान सरकार में मंत्री यादव (58) को सोमवार को एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल वरिष्ठ भाजपा नेता और नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे। यादव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का करीबी माना जाता है और उन्हें शीर्ष पद के दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा था।

15 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भजन लाल शर्मा

सरकार बनाने का दावा किया पेश

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेता भजन लाल शर्मा शुक्रवार 15 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह 56 वर्षीय ब्राह्मण नेता और पहली बार विधायक बने को पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। इससे पहले राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान राजनाथ सिंह और पसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राजभवन के एक बयान के अनुसार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्यपाल को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि शर्मा को राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। शर्मा के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थे। मनोनीत उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा भी उपस्थित थे। सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी ने उनके(भजनलाल शर्मा) नाम को विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है... उन्हें संगठन और पंचायती राज के चुनाव में काम करने का अनुभव है, निश्चित रूप से वे आगे प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह बहुत शानदार फैसला है। जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले इससे अच्छा और क्या हो सकता है... मैं भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं देता हूं, हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा और कानून व्यवस्था फिर से बहाल होगी।

अमित शाह ने नेहरू पर बोला हमला तो बचाव में उतरे राहुल

नईदिल्ली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की ओर से की गयी ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रही मोदी सरकार पर कांग्रेस आक्रामक हो गयी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि तीन परिवारों ने कश्मीर के अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पहले कई कानून उन पर लागू नहीं होते थे। इस पर भड़कते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी, सालों जेल में रहे। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं मालूम इसलिए ये बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई है।

जहां तक नेहरू की ओर से की गयी ऐतिहासिक गलतियों की बात है तो हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नेहरू के जमाने के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से उखाड़ फेंका था। यही नहीं देश की आजादी के समय पंडित नेहरू को जो पवित्र सेंगोल पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रदान किया गया था।

प्रमुख समाचार

चीन के बेल्ट एंड रोड से बाहर हुआ इटली

नई दिल्ली। इटली चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर हो गया है। बीआरआई के तहत चीन के साथ इटली का समझौता मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है और हाल ही में रोम से बीजिंग को एक पत्र भेजा गया था कि इसे नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ इटली साल 2019 में जुड़ा था। खास बात ये है कि चीन की सबसे महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक बीआरआई पर उस साल हस्ताक्षर करने वाला इटली एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश था। ऐसे में अब इस प्रोजेक्ट से इटली का पीछे हट जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीआरआई क्या है, इटली के बाहर निकलने के कारण और यह अभियान को कैसे प्रभावित कर सकता है। बीआरआई के नाम से मशहूर इस पहल को चीन में वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। यह अभियान 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति में एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश करना है।

आप ने भूमि आवंटन के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी को अपनी राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए कार्यालय बनाने में सक्षम बनाने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय रूप से स्थित क्षेत्रों को बाधाओं और अतिक्रमणों से मुक्त भूमि आवंटित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भूमि और विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया और याचिका को 23 अप्रैल, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अपनी याचिका में प ने दावा किया कि वह केंद्र द्वारा 31 जुलाई, 2014 को जारी नीतियों और 13 जुलाई, 2006 को मंत्रालय द्वारा जारी एक ज्ञापन के मद्देनजर कार्यालयों के निर्माण के लिए 1,000 वर्ग मीटर का हकदार है। याचिका के अनुसार, जुलाई 2006 का ज्ञापन दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय दलों को स्पष्ट रूप से 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान करता है। याचिका में कहा गया है कि इसमें दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है।

चुनाव आयुक्त बिल मोदी सरकार ने राज्यसभा से पास

नई दिल्ली। राज्यसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी। बीजू जनता दल (बीजद) के अमर पटनायक ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि भारत में अब तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती रही और आयोग ने सराहनीय काम किया है। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान का मूल ढांचा है- स्वतंत्र चुनाव एवं लोकतंत्र। लेकिन जब आयोग ही पूर्वाग्रह ग्रस्त होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे। इस साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), लोकसभा में विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए।

20 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी सीएम ममता

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य को वित्तीय बकाया जारी करने के लिए 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता ने दावा किया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1.15 लाख करोड़ रुपये बकाया है और भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार को या तो धन जारी करना चाहिए या कार्यालय खाली कर देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी से समय मांगा और अब वह अगले बुधवार को उनसे मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि मैं 17-20 दिसंबर के बीच दिल्ली जा रहा हूं। मैंने पीएम को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की लंबित धनराशि नहीं मिली है। अगर हर राज्य को उसके हिस्से का पैसा मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? बैठक में बनर्जी ने कहा, मैं कुछ सांसदों के साथ दिल्ली में रहूंगी। मैंने अपना बकाया दिलाने के लिए 18-20 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

कांग्रेस ने लगाया मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप

नईदिल्ली। भाजपा द्वारा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि यादव के खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कुछ गंभीर आरोप थे। इसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक एक्स पोस्ट साझा किया। अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा कि चुनाव परिणाम के आठ दिन बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना भी तो एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर उज्जैन मास्टरप्लान में बडे पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सिंहस्थ के लिए रिज़र्व 872 एकड़ ज़मीनों मे से उनकी ज़मीन को लैंड यूज़ बदलकर अलग किया गया। इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें यह गाली देते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते हुए दिख रहे हैं। क्या यह है मध्यप्रदेश के लिए 'मोदी की गारंटी'? इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देने आया था।

संशोधित आपराधिक कानून बिल लोकसभा में पेश

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है। सातवें दिन भी कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की गई और निर्णय भी लिए गए हैं। सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में सिलक्यारा सुरंग हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 पेश किए हैं। बिल पर 14 दिसंबर को चर्चा होगी और 15 दिसंबर को होने वाली बहस का जवाब दिया जाएगा। %विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2023% और %विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023% लोकसभा में पारित कर दिया गया।

लोकसभा की कार्यवाही

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' और 'केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' पेश किए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 के उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिहाज से संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करना जरूरी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों के मद्देनजर मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनो से संबंधित तीन विधेयकों को वापस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए। शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने नए विधेयकों को पेश किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है। अमित शाह ने कहा, '' मैंने तीनों विधेयकों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था। गृह मामलों की समिति ने कई सुझाव दिए थे। इतने सारे संशोधन लाने की जगह हमने नया विधेयक लाने का फैसला किया।''

लोकसभा ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा योजना और उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर दिया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी, जिसमें से 70,968 करोड़ रुपये को बचत और प्राप्तियों से समायोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा का जवाब दिया।

लोकसभा में कुछ सदस्यों ने रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये में रियायत एवं सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई। सदन में शून्यकाल के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी आने से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में छूट मिलती थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिये खेती को आसान बनाने की सरकार की योजना के तहत पूरे देश में 15,000 'नमो ड्रोन दीदी' को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान दी।

राज्यसभा की कार्यवाही

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के एक सदस्य ने विदेशी धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि पर मंगलवार को राज्यसभा में चिंता जताई और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों को विदेशी धरती पर तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है और वे देश के लिए खतरा बन रहे हैं।

राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाये गये विधेयक के कई प्रावधानों का तीखा विरोध करते हुए आशंका जतायी कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दावा किया कि इसके पीछे सरकार की मंशा निर्वाचन आयोग को 'जेबी चुनाव आयोग' बनाकर इसे अपनी मनमर्जी से चलाने की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023 पर उच्च सदन में चर्चा शुरू करते लेते हुए कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ''निष्पक्षता, निर्भीकता, स्वयात्तता और शुचिता'' चुनाव के आधारस्तंभ होते हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि संसद को ही कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के सुझावों के आधार पर यह विधेयक लेकर आई है।

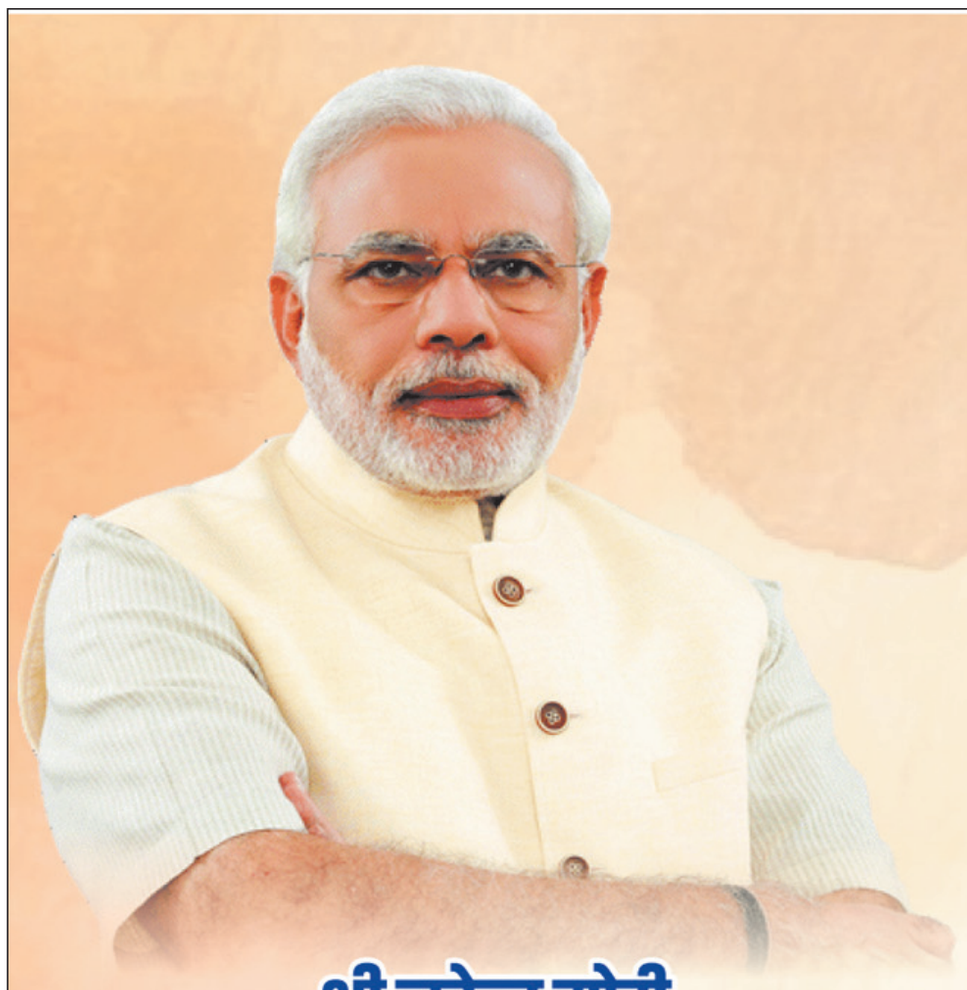

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ महतारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार

छत्तीसगढ़ के लिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की

गारंटी

तेंदूपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस

- हम प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण ₹ 5,500 प्रति मानक बोरा में करेंगे।
- वर्तमान संग्रहण अवधि में 15 दिनों की बढ़ोतरी की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त संग्राहकों को ₹ 4,500 तक बोनस, चरणपादुका एवं अन्य सुविधाएँ पुनः प्रदान की जाएंगी।

श्रीरामलला दर्शन

हम प्रदेशवासियों को हमारे आस्था के प्रतीक प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या लेकर जाएंगे।

दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना

हम 'दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना' की शुरुआत कर प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती

हम प्रदेश के 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित करेंगे।

500 में सिलेंडर

हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे, इससे महिलाओं को अपनी गृहस्थी चलाने में मदद मिलेगी।

संकल्प निभाएंगे
समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएंगे...

संवाद- 39073/124

सबका साथ - सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 दिसंबर को होगा। राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। इसके लिए तैयारी जोरों पर है।

शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी जोरों पर हैं। वहीं सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता, नेता समेत विधायक भी मौजूद है7 इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी मौजूद हैं। वे सभी तैयारियों का जाएजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में आने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसमें एडीजी स्तर के एक आधिकारी और आईजी स्तर के चार अधिकारियों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ ही दो डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल भी शपथ ले सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है। इसका इंतजार प्रदेश की जनता को भी है, हालांकि मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर मंथन जारी है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया,

भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन समेत दूसरे राज्यों मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

विष्णुदेव साय को रविवार को विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद से उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं, सोमवार को विष्णुदेव साय भगवान श्रीराम के दर्शन करने के लिए रायपुर में स्थित राम मंदिर पहुंचे। विष्णुदेव साय ने विधि-विधान से भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। साय ने भगवान राम से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए कामना की।

इस इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रायपुर पंडरी स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद साय नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का आमंत्रण देंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को शपथ ग्रहण समारोह में किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को आज टेलीफोन किया है। 13 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, विशिष्टजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि बुधवार को शहर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। दोपहर 2 बजे नवनियुक्त सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को देखते हुए मुख्य डोम के साथ तीन अन्य डोम भी तैयार किए जा रहे हैं। तीन बड़े डोम के साथ एक मुख्य मंच भी तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड में अलग-अलग जिलों के पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अरुण साव ने विपक्षी नेता समेत जनता को किया आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण करने पर कहा, पूरे छग को आमंत्रित किया है तो विपक्ष के नेता भी आमंत्रित है। राजनीतिक और धार्मिक संगठन को समारोह के साक्षी बने आमंत्रित करता हूं। कितने लोग शपथ लेंगे इस पर अरुण साव ने कहा कि कितने लोग शपथ लेंगे यह समय पर पता चल जायेगा। जनता को किस तरह से साधेंगे इसपर अरुण साव ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है। संगठन के काम और समाजसेवा में सबका उपयोग करने वाले है। मिशन 2024 को लेकर अरुण साव ने कहा, एक-एक कार्यकर्ता संकल्पित है। 11 लोकसभा सीटें पीएम मोदी की झोली में डालने के लिये। दीपक बैज के कार्रवाई वाले बयान पर साव बोले, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। जिस प्रकार की बातें आई है। छग की जनता को पांच साल तक इन्होंने ठगा है। शपथ ग्रहण समारोह पर अरुण साव ने कहा, छग की जनता ने वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से बीजेपी को ऐतिहासिक जनमत दिया है। कल शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होने वाला है। समारोह में आशीर्वाद देने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री व नेता आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ भर से सभी प्रतिष्ठित जन उपस्थित रहेंगे, सभी को आमंत्रित करता हूं।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की होगी पूरी जांच : विधायक विजय शर्मा

रायपुर। कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार में योजनाओं में हुई भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जांच होगी, सभी विषयों पर निर्णय होना है। साथ ही विजय शर्मा ने मंत्रिमंडल की घोषणा पर कहा, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनकी इच्छा के ऊपर है। चाहे शपथ के पहले या शपथ के बाद। कांग्रेस के झीरम हमले की जांच वाले बयान पर विधायक विजय शर्मा ने कहा कि कोई व्यक्ति यह कह सकता है क्या बीजेपी आ गई अब जांच करे। कांग्रेस ने पांच साल में जांच क्यों नहीं किया। सबूत तो भूपेश बघेल के जेब में था। सरकार आते ही अपने सरकार में क्यों नहीं दे दिए। उमेश पटेल को लेकर विजय शर्मा ने कहा पिताजी के हत्यारों का पता करो, मंत्री बनकर क्यों बैठे रहे? विजय शर्मा ने मीसाबंदियों के लिए पेंशन योजना पर कहा कि मीसाबंदियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया था, अन्य पार्टियों के लोगों को भी यह सुविधा मिल रही थी।

राज्यपाल हरिचंदन से नामित मुख्यमंत्री साय ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में नामित मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियों एवं प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साय ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शाल भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने भी श्री साय को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया।

नए मुख्यमंत्री के गृहग्राम बगिया में उत्सव का माहौल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए सीएम के लिए विष्णुदेव साय का नाम फायनल होते ही उनके गृह गांव बगिया समेत आसपास के गांवों में जश्न का महौल है। श्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आम से लेकर वीआईपी लोग नए सीएम के घर बधाई देने पहुंच रहे हैं। साथ ही लोग लगातार आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं।लोक गीतों की धुन में थिरके लोग- जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, फरसाबहार सहित जिले भर के ग्रामीण अंचल के लोग जश्न में सराबोर हैं। लोग जशपुर के माटी पुत्र और आदिवासी समाज के नेता विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की खुशियां मना रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लोक गीतों की धुन में नृत्य का दौर चल रहा है। लोग अपने अपने गांव में इकट्ठे होकर सुबह से रात तक जश्न मना रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गौतम लुंकड ने दिया पार्टी से इस्तीफा

कांकेर। जिले में विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कांकेर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गौतम लुंकड़ ने पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौतम लुंकड़ ने इस्तीफा राजीव भवन के कार्यालय में दिया और कर्मचारी के आग्रह के बावजूद भी अध्यक्ष से नही मिलने की नाराजगी जताई। इस्तीफे का कारण, पार्टी की ओर से अनदेखी और निरंतर उपेक्षा करना बताया गया है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज राजीव भवन में

रायपुर। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक बुधवार 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे राजीव भवन में आयोजित की गयी है। इस बैठक में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का हुआ अंतः अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस के दावों को लेकर कांग्रेसी नेताओं को घेर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है।

मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत मिली है। वोट प्रतिशत के हिसाब से हो या सीटों के हिसाब से, ऐतिहासिक जीत मिली है। निश्चित रूप से कांग्रेस से कुशासन का अंत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ अब खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा।आदिवासी सीएम बनाने पर बोले साव- आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अरुण साव ने कहा, विष्णु देव साय एक अनुभवी नेता हैं। प्रशासनिक अनुभव है, संगठन में भी काम करने का अनुभव है, एक अनुभवी चेहरे को पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंपा है। निश्चित रूप से विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव में दी गई मोदी की गारंटी को पूरा करने की तैयारी शुरू करने की बात साव ने कही है।

10 दिसंबर को रायपुर में हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को अपना नेता चुन लिया गया है। जिसके बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। 13 दिसंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। जहां विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

साय को मुख्यमंत्री बनने पर कंवर समाज ने दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरवंश मिरी सहित उपाध्यक्ष श्रीमती सविता साय, श्री थानसिंह दीवान, डॉ संदीप ठाकुर, श्री उपेंद्र सिँह पैकरा, श्री हरिराम पूजेरी, महासचिव श्री नकुल चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष श्री बसंत दीवान, सह सचिव श्रीमती धनेशवरी कंवर, अधिवक्ता श्री कुंजबिहारी सिंह, कार्यकारिणी सदस्य श्री टीकाराम कंवर सहित महानगर रायपुर के अध्यक्ष श्री मनोहर पैकरा, सचिव श्री मनहरण पैकरा, श्री छत्रपाल सोनवानी, श्री ललित दीवान सहित समस्त जिलों के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों द्वारा श्री विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति कंवर आदिवासी समाज से माटी पुत्र को मुख्यमंत्री बनायें जाने पर कृतज्ञता सहित धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कंवर समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश मिरी ने कहा है कि उन्हें विश्वास था कि साय साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और जब से श्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनाये जाने की घोषणा हुई है तब से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में रहने वाले कंवर समाज बहुत ज्यादा खुश है एवं जिलों में खुशियाँ मना रहें है। श्री मिरी ने आगे कहा है कि श्री विष्णुदेव साय के राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद समाज के प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलों के पदाधिकारी सहित अन्य प्रदेश के कंवर समाज पदाधिकारियों द्वारा समाज के किसान एवं माटी पुत्र से मिल कर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी जावेगी एवं समाज के प्रथम मुख्यमंत्री बनने पर उनका सम्मान भी किया जावेगा।

नवनियुक्त मुख्यमंत्री से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने की मुलाकात

छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को राजधानी रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुंना में प्रदेश भर से आये विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने भेंटकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय से भेंट करने वालों में उनके गृह जिले जशपुर से आए विभिन्न जनजातीय सामाजिक संगठन, अन्य समाज के प्रतिनिधिमंडल के अलावा प्रदेश के सभी जिलों से आए विभिन्न सामाजिक सगठनों के लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनसे मिलने आए सभी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में कंवर समाज, उरांव समाज, गोंड समाज, अघरिया समाज, रौनियार समाज, यादव समाज के साथ अन्य समाज के लोग मौजूद रहे।

नए मुख्यमंत्री आदिवासी इलाकों की चुनौतियों, परिस्थितियों और मनोभाव को समझेंगे : नेताम

■ पूर्व केंद्रीय मंत्री नेताम ने जनजाति समाज से मुख्यमंत्री चुने जाने पर जताई प्रसन्नता, नए मुख्यमंत्री साय को दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद नेताम ने श्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने खास तौर पर देश के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा है कि जनजाति क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने जाने से वह आदिवासी इलाके की चुनौतियों, परिस्थितियों और मनोभाव को समझेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री श्री साय जनजाति समाजों से बातचीत कर आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति देंगे।

श्री नेताम ने कहा कि जनजाति समाज से श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना और छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज से श्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना समाज के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के लोग कम कहते है और करते अधिक हैं। इसी तरह नए मुख्यमंत्री श्री साय भी काम करेंगे। वे जनजाति समाज से होने के कारण समाज के मनोभाव को समझेंगे। श्री नेताम ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री और मंत्रीमण्डल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण मिला है, जिसमें वे शामिल होंगे।

श्री नेताम ने कहा कि आदिवासी इलाके के विकास के लिए उन्हें अन्य क्षेत्रों से अलग देखना आवश्यक है। सामान्य तौर पर विकास को औद्योगीकरण से मापा जाता है। अवधारणा है कि औद्योगीकरण होगा तो विकास होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जनजाति समाज की भावना को गहराई से समझेंगे और उनसे बातचीत कर आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास की नई राह गढ़ेंगे। नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले सालों में जनजाति समाज के विकास को लेकर उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। सरकार और जनजाति समाज के बीच संवादहीनता रही है। श्री विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से उम्मीद है कि यह संवादहीनता खत्म होगी।

नई सरकार से उम्मीदें

पूर्व केंद्रीय मंत्री नेताम ने कहा कि कल कारखाने विकास के लिए जरूरी हैं। प्राकृतिक संसाधनों को अगर नष्ट नहीं कर विकास किया जाए तो वहीं विकास सच्चा विकास होता है। नई सरकार से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। नई सरकार जनजातीय समाज की भावना का ख्याल रखेगी और विकास विनाश के नाम पर नहीं होगा ये उम्मीद है। आदिवासी क्षेत्र जो विकास की राह में पिछड़ गए हैं उनको तरक्की की राह पर ले जाना जरूरी है।

उज्जवला योजना के हितग्राहियों को मिलेगा ही मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर

पर कराना होगा 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी

रायपुर। पांच सौ रुपये में सिलेंडर मिलने की आस में उपभोक्तों घंटों तक गैस एजेंसियों के दरवाजे पर खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि सिर्फ उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी उज्जवला गैस कनेक्शनधारक को संबंधित गैस एजेंसी में ई-केवाईसी करवाना जरूरी है।

जिले में 35 गैस एजेंसियां हैं, जहां सुबह से ही ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। लाइन में घंटों इंतजार करने के बाद जब लोगों का नंबर आ रहा है तो उन्हें सर्वर डाउन होने की जानकारी मिल रही है। इससे मायूस लोग बिना ई-केवाईसी कराए ही घर लौट रहे हैं। मायूस और गुस्साए उपभोक्ता कई बार एजेंसी के संचालकों से वाद-विवाद करने लग जाते हैं। उनका आरोप रहता है कि एजेंसी वाले ई-केवाईसी करने के बजाय जनता को घुमा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से 31 दिसंबर तक सभी उपभोक्ताओं को ई केवायसी करवाने का अल्टीमेटम दिया गया है। हितग्राहियों को डर है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं हो पाई तो वे लाभ से वंचित हो जाएंगे। यही कारण है कि वह लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने में लगे हुए हैं।

खाद्य नियंत्रक केसी थारवानी ने बताया कि सिर्फ उज्जवला हितग्राहियों को ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में मिले निर्देशों के अनुसार जो सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं, वह सिर्फ उज्जवला के हितग्राहियों को ही दिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के लिए मंथन

■ चरणदास महंत और उमेश पटेल रेस में आगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ी पटखनी दी। उसके बाद से कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हार को लेकर दिल्ली और रायपुर में मंथन का दौर चला। पूरी कांग्रेस पार्टी में हार के कारणों पर मीटिंग हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर दो बजे से होगी।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में होगी मीटिंग

बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर दो बजे रायपुर में बुलाई गई है। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की मीटिंग होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम और पाटन से कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल, सक्ती से कांग्रेस विधायक चरणदास महंत, खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल समेत तमाम नेता मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बड़ी बैठक का हिस्सा होंगे।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की रेस

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में इस बार ओबीसी समुदाय के नेता पहली पसंद बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इसमें सक्ती से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम सबसे पहले है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है। इन सब नेताओं में दलेश्वर साहू का भी नाम तेजी से आगे आ रहा है। साल 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करे तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस 35 सीटों पर आकर सिमट गई। जबकि उसे साल 2018 के चुनाव में कुल 68 सीटें मिली थी। बीजेपी को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 54 सीटें मिली है। वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के नौ मंत्रियों और कई बड़े नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जबकि चुनाव जीतने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उमेश पटेल और अनिला भेंडिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत शामिल हैं

भाजपा सरकार पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेः कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया कि भाजपा सरकार पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के 2 लाख तक के कर्जा माफ करने की घोषणा करें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के अनेकों नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के कर्जमाफी करने का वायदा अपने भाषणों में किया था, इस संबध में पाम्पलेट भी वितरित किया गया था।

भाजपा नेता विजय शर्मा का चुनाव प्रचार का वीडियों भी शोसल मीडिया में वायरल है। जिसमें वे 2 लाख कर्जमाफी का वायदा कर रहे है। विजय शर्मा भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक है ऐसी संभावना भी बतायी जा रही है कि वे भाजपा के सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाये जा रहे है उन्होंने चुनाव के दौरान कवर्धा की जनता से अनेक जगह सभाओं में वादा किया है, कि भाजपा की सरकार बनने पर 2 लाख तक सारे बड़े और छोटे किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा। अब भाजपा की सरकार बन गयी है। किसान अपेक्षा कर रहे है कि विजय शर्मा पहले कैबिनेट के बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराये कि 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ होगा जैसा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अनेक सभा में भाजपा ने जनता से वायदा किया था।

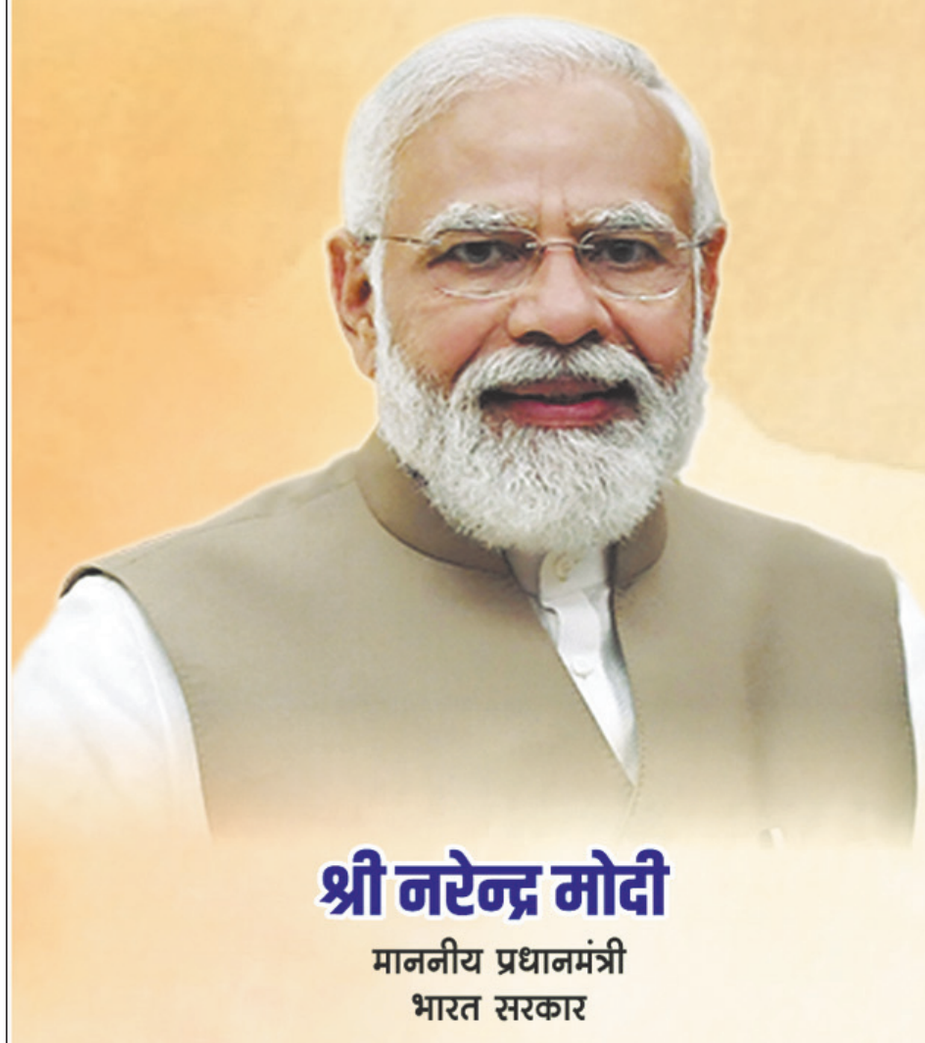

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार

छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ महतारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

छत्तीसगढ़ के लिए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की
गारंटी

कृषक उन्नति योजना

हम "कृषक उन्नति योजना" की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गतः
- 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ₹ 3,100 में की जाएगी।
- किसानों का पैसा बिना लम्बी कतारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित करेंगे।
- प्रदेश में धान खरीद से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

महतारी वन्दन योजना

हम 'महतारी वन्दन योजना' की शुरुआत कर प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को ₹ 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर-घर निर्मल जल अभियान

हम अपनी पहली 'कैबिनेट बैठक' में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करेंगे एवं 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाएंगे।

बोनस की गारंटी

सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2023 को किसान भाइयों को मिलेगा 2 वर्ष का बकाया धान बोनस

पी.एस.सी. परीक्षा में पारदर्शिता

हम राज्य में सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को UPSC की तर्ज पर सुव्यवस्थित करेंगे, ताकि भविष्य में सभी शासकीय भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का समावेश हो।

विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़

नयी सुबह, नयी सोच

अब होगा विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण

संवाद- 39073/124

सबका साथ - सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.